

कोर्ट कॉलेजियम

संदर्भ: हाल ही में सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम ने राजस्थान, उत्तराखंड और इलाहाबाद उच्च न्यायालयों में चार न्यायिक अधिकारियों की नियुक्ति और एक वकील को न्यायाधीश के पद पर पदोन्नत करने की सिफारिश की।

नियुक्ति हेतु अनुशंसित व्यक्ति:

- कॉलेजियम ने निम्नलिखित न्यायिक अधिकारियों और एक वकील के नाम को पदोन्नति हेतु प्रस्तावित किया:
 - आशीष नैथानी:** उत्तराखंड उच्च न्यायालय में न्यायाधीश के पद के लिए अनुशंसित।
 - प्रवीण कुमार गिरि:** इलाहाबाद उच्च न्यायालय में न्यायाधीश के पद के लिए अनुशंसित (वकील से पदोन्नति)।
 - चन्द्रशेखर शर्मा:** राजस्थान उच्च न्यायालय में न्यायाधीश के पद के लिए अनुशंसित।
 - प्रमिल कुमार माथुर:** राजस्थान उच्च न्यायालय में न्यायाधीश के पद के लिए अनुशंसित।
 - चन्द्र प्रकाश श्रीमाली:** राजस्थान उच्च न्यायालय में न्यायाधीश के पद के लिए अनुशंसित।

उच्च न्यायालयों में वर्तमान रिक्तियां:

- राजस्थान उच्च न्यायालय:** न्यायालय में न्यायाधीशों के स्वीकृत पद 50 हैं, लेकिन वर्तमान में केवल 32 न्यायाधीशों के साथ कार्य कर रहा है, जिसके परिणामस्वरूप 18 न्यायाधीशों के पद रिक्त हैं।
- इलाहाबाद उच्च न्यायालय:** 160 न्यायाधीशों के स्वीकृत पद के साथ, न्यायालय केवल 81 न्यायाधीशों के साथ कार्य कर रहा है, जिससे 79 न्यायाधीशों के पद रिक्त हैं।
- उत्तराखंड उच्च न्यायालय:** 11 न्यायाधीशों के स्वीकृत पद वाले इस न्यायालय में वर्तमान में केवल छह न्यायाधीश हैं, जिसमें पांच न्यायाधीशों का पद रिक्त है।

भारत में कॉलेजियम प्रणाली के बारे में:

- कॉलेजियम प्रणाली भारत में सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालयों में न्यायाधीशों की नियुक्ति और स्थानांतरण की एक विधि है। यह संविधान का हिस्सा नहीं है, लेकिन यह न्यायिक निर्णयों के माध्यम से विकसित हुई है।
- इस प्रणाली में भारत के मुख्य न्यायाधीश (CJI) और सर्वोच्च न्यायालय के वरिष्ठ न्यायाधीश नियुक्तियों और स्थानांतरण की सिफारिश करते हैं, जिसमें अंतिम निर्णय कार्यपालिका के परामर्श के बाद बाध्यकारी होता है।

कॉलेजियम सिस्टम कैसे काम करता है?

- सुप्रीम कोर्ट में, CJI, चार वरिष्ठतम न्यायाधीशों के साथ मिलकर

न्यायाधीशों की नियुक्ति और स्थानांतरण की सिफारिश करता है। इसी तरह, उच्च न्यायालयों में, मुख्य न्यायाधीश और दो वरिष्ठतम न्यायाधीश न्यायिक नियुक्तियों के लिए कॉलेजियम बनाते हैं। सरकार आपत्ति उठा सकती है, लेकिन अगर कॉलेजियम अपनी सिफारिशों को दोहराता है, तो सरकार को अनुशंसित न्यायाधीशों की नियुक्ति करनी होगी।

न्यायिक नियुक्तियों के लिए संवैधानिक प्रावधान:

- अनुच्छेद 124:** सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा मुख्य न्यायाधीश और अन्य आवश्यक न्यायाधीशों के परामर्श के बाद की जाती है।
- अनुच्छेद 217:** उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा मुख्य न्यायाधीश, राज्य के राज्यपाल और संबंधित उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के परामर्श के बाद की जाती है।

कॉलेजियम प्रणाली की उत्पत्ति :

कॉलेजियम प्रणाली सुप्रीम कोर्ट के कई निर्णयों से उभरी है:

- एस.पी. गुप्ता केस (1981):** परामर्श को विचारों के आदान-प्रदान के रूप में व्याख्यायित किया गया, जिसमें सहमति की आवश्यकता नहीं थी।
- द्वितीय न्यायाधीश मामला (1993):** न्यायालय ने अपने पहले के रुख को पलटते हुए फैसला सुनाया कि परामर्श का मतलब सहमति है और मुख्य न्यायाधीश की सलाह राष्ट्रपति के लिए बाध्यकारी है।
- तृतीय न्यायाधीश मामला (1998):** इसने न्यायिक नियुक्तियों के लिए सर्वोच्च न्यायालय के चार वरिष्ठतम न्यायाधीशों को शामिल करने के लिए कॉलेजियम का विस्तार किया।

घरेलू उपभोग व्यय सर्वेक्षण (एचसीईएस)

2023 - 24

संदर्भ: हाल ही में जारी घरेलू उपभोग व्यय सर्वेक्षण (HCES) 2023-24 में पूरे भारत के खाद्य व्यय और उपभोग पैटर्न में महत्वपूर्ण रुझान सामने आए हैं। एक दशक से अधिक की गिरावट के बाद, भारतीय परिवारों में खाद्य व्यय में वृद्धि हुई है। 2023-24 में, ग्रामीण परिवारों ने अपने व्यय का 47.04% भोजन पर खर्च किया, जोकि पिछले वर्ष के 46.38% से अधिक है, जबकि शहरी परिवारों में भी इसी तरह की वृद्धि देखी गई और यह 39.17% से बढ़कर 39.68% हो गया। खाद्य व्यय में यह वृद्धि खाद्य कीमतों में उछाल के कारण हुई है, जिसने पूरे देश में खपत को प्रभावित किया है।

बढ़ती खाद्य कीमतों का उपभोग पर प्रभाव:

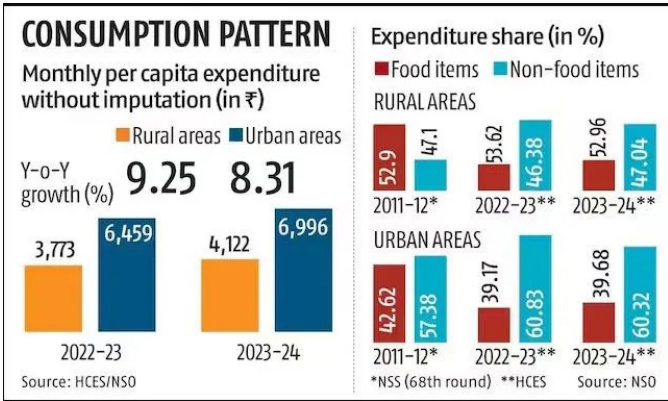
- खाद्य व्यय में वृद्धि से स्पष्ट होता है कि खाद्य पदार्थों की बढ़ती कीमतों ने घरेलू बजट पर काफी दबाव डाला है। विशेष रूप से ग्रामीण क्षेत्रों में, उपभोग व्यय में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है, जिसने शहरी और ग्रामीण

उपभोग पैटर्न के बीच की खाई को कम किया है।

- यह बदलाव उपभोग व्यवहार में एक महत्वपूर्ण बदलाव को दर्शाता है, जो नीति निर्माताओं और अर्थशास्त्रियों के लिए यह समझने के लिए महत्वपूर्ण है कि बढ़ती कीमतें भारत भर में विभिन्न जनसांख्यिकीय समूहों को कैसे प्रभावित करती हैं।

ग्रामीण और शहरी उपभोग व्यय में हालिया रुझान :

- 2023-24 में, ग्रामीण परिवारों का औसत मासिक प्रति व्यक्ति व्यय (एमपीसीई) 4,122 रुपये रहा, जो पिछले वर्ष की तुलना में 9.3% की वृद्धि दर्शाता है। इसके विपरीत, शहरी परिवारों का औसत एमपीसीई 6,996 रुपये रहा, जो 8.3% की मामूली वृद्धि को दर्शाता है। ग्रामीण उपभोग व्यय में वृद्धि दर शहरी क्षेत्रों से अधिक रही, जिससे ग्रामीण और शहरी उपभोग स्तरों के बीच का अंतर और कम हो गया।



घटती उपभोग असमानता :

- ग्रामीण और शहरी परिवारों के बीच उपभोग असमानता में कमी आई है, जैसा कि दोनों क्षेत्रों के गिनी गुणांक में देखा जा सकता है। 2023-24 में, ग्रामीण गिनी गुणांक 0.266 से घटकर 0.237 हो गया, जबकि शहरी गिनी गुणांक 0.314 से घटकर 0.284 हो गया।
- यह गिरावट असमानता में कमी का संकेत देती है, जो यह सुझाव देती है कि ग्रामीण और शहरी परिवारों के बीच आर्थिक अंतर कम हो रहा है, और ग्रामीण उपभोग शहरी उपभोग की तुलना में तेजी से बढ़ रहा है।

खाद्यान्न व्यय पैटर्न में परिवर्तन:

- 2023-24 में विशिष्ट खाद्य पदार्थों पर व्यय के हिस्से में भी बदलाव आया है। ग्रामीण और शहरी दोनों ही परिवारों ने अनाज, अंडे, मछली और मांस पर अधिक खर्च किया।
- उल्लेखनीय यह है कि पेय पदार्थ, स्नैक्स और प्रसंस्कृत खाद्य पदार्थ सबसे अधिक व्यय वाली श्रेणियां बनी रहीं, जिसमें ग्रामीण परिवारों ने इन वस्तुओं पर अपने कुल उपभोग का 9.84% और शहरी परिवारों ने 11.09% खर्च किया। यह ग्रामीण और शहरी दोनों ही आबादी में बदलते

खान-पान के रुझान और प्राथमिकताओं को दर्शाता है।

क्षेत्रीय और आय समूह भिन्नताएं:

- आय समूहों और क्षेत्रों के अनुसार उपभोग व्यय में काफी भिन्नता देखी गई। ग्रामीण और शहरी दोनों क्षेत्रों में निम्न आय वाले 5% लोगों ने व्यय में उल्लेखनीय वृद्धि (ग्रामीण क्षेत्रों में 19.2%, शहरी क्षेत्रों में 18%) दर्ज की, जबकि उच्च आय वाले 5% लोगों ने कमी दर्ज की।
- क्षेत्रीय स्तर पर, महाराष्ट्र, पंजाब और केरल जैसे राज्यों ने औसत से अधिक व्यय प्रदर्शित किया, जबकि पश्चिम बंगाल, बिहार और उत्तर प्रदेश जैसे राज्यों में औसत से कम उपभोग व्यय रहा। ये क्षेत्रीय असमानताएं देश के भीतर आर्थिक असमानता को उजागर करती हैं।

चालू खाता घाटा (सीएडी) में कमी

सन्दर्भ: हाल ही में वित्त वर्ष 2024-25 की दूसरी तिमाही में भारत का चालू खाता घाटा मामूली रूप से घटकर 11.2 बिलियन डॉलर हो गया है, जोकि सकल घरेलू उत्पाद (GDP) का 1.2% है। यह पिछले वर्ष की इसी तिमाही में दर्ज 11.3 बिलियन डॉलर (GDP का 1.3%) घाटे की तुलना में मामूली सुधार है। यह स्थिर आंकड़ा दर्शाता है कि घाटा बना हुआ है, लेकिन यह GDP के प्रतिशत के रूप में अपेक्षाकृत स्थिर रहा है।

चालू खाता घाटा (CAD) क्या है?

- चालू खाता घाटा किसी देश के माल और सेवाओं के आयात और निर्यात के बीच के अंतर को दर्शाता है। जब एक देश जितना निर्यात करता है उससे अधिक आयात करता है, तो वह चालू खाता घाटे का सामना करता है। यह दर्शाता है कि देश विदेशों से अधिक खरीद रहा है जितना वह बेच रहा है। चालू खाता घाटा किसी देश की अर्थव्यवस्था के स्वास्थ्य का एक महत्वपूर्ण संकेतक है और यह विदेशी मुद्रा भंडार पर दबाव डालता है।

चालू खाता घाटा: प्रवृत्ति H1 FY2024-25

- वित्त वर्ष 2024-25 की पहली छमाही (अप्रैल-सितंबर) के लिए, चालू खाता घाटा 21.4 बिलियन डॉलर रहा, जो सकल घरेलू उत्पाद (GDP) का 1.2% है। यह वित्त वर्ष 2023-24 की पहली छमाही में दर्ज 20.2 बिलियन डॉलर (GDP का 1.2%) से लगभग अपरिवर्तित है। यह स्थिर आंकड़ा दर्शाता है कि हालांकि घाटा जारी है, लेकिन यह पिछले वर्ष की तुलना में सकल घरेलू उत्पाद के प्रतिशत के रूप में अपेक्षाकृत स्थिर रहा है।

चालू खाता घाटे के प्रमुख कारक:

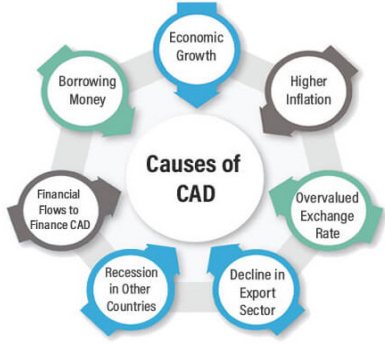
- वस्तु व्यापार घाटा:** वस्तु व्यापार घाटे में वृद्धि ने चालू खाता घाटे में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। वित्त वर्ष 2024-25 की दूसरी तिमाही में, वस्तु व्यापार घाटा पिछले वित्त वर्ष के 64.5 बिलियन डॉलर से बढ़कर



30 December 2024

75.3 बिलियन डॉलर हो गया।

- **सेवा निर्यात:** कंप्यूटर सेवाओं, व्यावसायिक सेवाओं और परिवहन जैसे क्षेत्रों में मजबूत वृद्धि के कारण सेवा निर्यात में वृद्धि हुई है, जिसने चालू खाता घाटे को कम करने में मदद की है।
- **विदेशी मुद्रा प्रेषण:** विदेशों में भारतीय श्रमिकों से प्राप्त धन में वृद्धि हुई है, जिसने CAD में कमी लाने में योगदान दिया है।



विदेशी निवेश और अनिवासी जमा राशियों में रुझान:

- प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (FDI) में वित्त वर्ष 2024-25 की दूसरी तिमाही में 2.2 बिलियन डॉलर का शुद्ध बहिर्वाह देखा गया, जबकि वित्त वर्ष 2023-24 की दूसरी तिमाही में 0.8 बिलियन डॉलर का बहिर्वाह देखा गया था।
- विदेशी पोर्टफोलियो निवेश (FPI) का प्रवाह बढ़कर 19.9 बिलियन डॉलर हो गया, जो पिछले वर्ष के 4.9 बिलियन डॉलर से उल्लेखनीय वृद्धि है।
- अनिवासी भारतीय (NRI) जमा राशियों में भी वृद्धि देखी गई, जिसमें शुद्ध अंतर्वाह एक वर्ष पहले के 3.2 बिलियन डॉलर से बढ़कर 6.2 बिलियन डॉलर हो गया।

विदेशी मुद्रा भंडार पर प्रभाव:

- भारत के विदेशी मुद्रा भंडार में वित्त वर्ष 2024-25 की दूसरी तिमाही में 18.6 बिलियन डॉलर की उल्लेखनीय वृद्धि देखी गई, जोकि वित्त वर्ष 2023-24 की दूसरी तिमाही में 2.5 बिलियन डॉलर की वृद्धि से काफी अधिक है। यह दर्शाता है कि भारत के पास अधिक विदेशी मुद्रा है, जो देश को बाहरी झटकों से बचाने में मदद करती है और रुपये के मूल्य को स्थिर रखने में मदद करती है।

जयशंकर और ब्लिंकन ने अमेरिका - भारत साझेदारी की समीक्षा की

सन्दर्भ: हाल ही में भारतीय विदेश मंत्री एस. जयशंकर ने अमेरिका-भारत साझेदारी की प्रगति की समीक्षा करने के लिए वाशिंगटन डीसी में

अमेरिकी विदेश मंत्री एंटीनी ब्लिंकन से मुलाकात की। चर्चा का उद्देश्य दोनों देशों के बीच चल रहे सहयोग का आकलन करना और प्रौद्योगिकी, व्यापार, निवेश को बढ़ावा देना और प्रवासी भारतीयों के लिए सेवाओं में सुधार हेतु संबंधों को और मजबूत करना है।

भारत के लिए संयुक्त राज्य अमेरिका महत्व:

- भारत के आर्थिक, रणनीतिक, तकनीकी और भू-राजनीतिक परिदृश्य में संयुक्त राज्य अमेरिका की भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण है। वर्ष 2024 में, अमेरिका भारत का प्रमुख व्यापारिक साझेदार बना हुआ है, जिसके साथ द्विपक्षीय माल व्यापार 72 बिलियन डॉलर से अधिक हो गया है। आर्थिक संबंध आईटी सेवाओं, फार्मास्यूटिकल्स और उभरती प्रौद्योगिकियों जैसे क्षेत्रों में गहरे होते जा रहे हैं, जिनमें भविष्य में और अधिक विकास की अपार संभावनाएं हैं।
- अमेरिका-भारत रक्षा सहयोग अब बुनियादी स्तर के समझौतों से आगे बढ़कर सैन्य हार्डवेयर के सह-विकास तक पहुंच गया है। क्वाड जैसी पहलों ने इस सहयोग को और मजबूत बनाया है। ऊर्जा के क्षेत्र में भी अमेरिका भारत का एक प्रमुख साझेदार है और भारत के स्वच्छ ऊर्जा लक्ष्यों को प्राप्त करने में सहायता कर रहा है। इसके अतिरिक्त, दोनों देश अंतरिक्ष अनुसंधान, स्वास्थ्य सेवा, शिक्षा और डिजिटल विकास जैसे क्षेत्रों में सहयोग कर रहे हैं। इस द्विपक्षीय संबंध के माध्यम से भारत अपनी रणनीतिक स्वायत्तता को बनाए रखने में सक्षम हुआ है।

भारत-अमेरिका संबंधों में प्रमुख मुद्दे क्या हैं ?

भारत-अमेरिका संबंधों में कई चुनौतियाँ बनी हुई हैं, जिनमें शामिल हैं:

- **व्यापार संबंधों में तनाव:** टैरिफ, बाजार पहुंच और बौद्धिक संपदा अधिकारों जैसे मुद्दों पर मतभेद व्यापार संबंधों को प्रभावित करते हैं।
- **रणनीतिक स्वायत्तता:** भारत की स्वतंत्र विदेश नीति, विशेषकर रूस और मध्य पूर्व के साथ संबंधों को लेकर अमेरिका के साथ मतभेद हैं।
- **डिजिटल गवर्नेंस:** डेटा संरक्षण और स्थानीयकरण नीतियों को लेकर दोनों देशों के बीच मतभेद हैं जोकि अमेरिकी तकनीकी कंपनियों के लिए चुनौतियाँ पैदा करते हैं।
- **बीजा और आब्रजन मुद्दे:** एच-1बी बीजा पर प्रतिबंध और ग्रीन कार्ड प्रसंस्करण में देरी भारत के आईटी क्षेत्र को प्रभावित करती है।
- **चीन कारक:** चीन के उदय को लेकर दोनों देशों के अलग-अलग दृष्टिकोण हैं, जिसके कारण रणनीतिक अनिश्चितताएं बढ़ती हैं।
- **जलवायु और ऊर्जा नीति:** जलवायु परिवर्तन से निपटने के लिए दोनों देशों के अलग-अलग दृष्टिकोण हैं, विशेषकर वित्तीय सहायता और कार्बन उत्सर्जन को कम करने के तरीकों को लेकर।

दोनों देशों के लिए भविष्य की संभावनाएं:

भारत-अमेरिका संबंध में कई क्षेत्रों में सहयोग को गहरा करने की अपार संभावनाएं हैं:

Face to Face Centres



30 December 2024

- **रक्षा प्रौद्योगिकी:** युद्ध में एआई, हाइपरसोनिक्स जैसी अगली पीढ़ी की प्रौद्योगिकियों और भारत में संयुक्त रक्षा उत्पादन सुविधाओं पर ध्यान केंद्रित करके सामरिक संप्रभुता बढ़ाई जा सकती है।
- **ऊर्जा सुरक्षा:** एलएनजी, नवीकरणीय ऊर्जा और ऊर्जा भंडारण अनुसंधान में संयुक्त पहल से दोनों देशों की ऊर्जा आवश्यकताओं को पूरा किया जा सकता है।
- **डिजिटल अर्थव्यवस्था:** सामान्य डेटा गोपनीयता मानकों, संयुक्त फिनटेक पहलों और डिजिटल सुरक्षा ढांचे को विकसित करके व्यापार और सहयोग को बढ़ावा मिल सकता है।
- **स्वास्थ्य देखभाल:** संयुक्त वैक्सीन उत्पादन, टेलीमेडिसिन और उभरती बीमारियों पर अनुसंधान से वैश्विक स्वास्थ्य सुरक्षा में सुधार होगा।
- **जलवायु कार्रवाई:** एक संयुक्त कार्बन व्यापार तंत्र और हरित प्रौद्योगिकी हस्तांतरण दोनों देशों को आर्थिक अवसर पैदा करते हुए जलवायु लक्ष्यों को पूरा करने में मदद कर सकता है।
- **शैक्षिक और अनुसंधान सहयोग:** एआई, क्वांटम कंप्यूटिंग और जैव प्रौद्योगिकी जैसे क्षेत्रों में संयुक्त डिग्री कार्यक्रमों और अनुसंधान केंद्रों का विस्तार नवाचार को बढ़ावा देगा और वैश्विक चुनौतियों का समाधान करेगा।

पावर पैकड न्यूज

चीनी अंतरिक्ष यात्रियों ने बनाया सबसे लंबा स्पेसवॉक का नया रिकॉर्ड

- चीन के दो अंतरिक्ष यात्रियों ने तियांगोंग अंतरिक्ष स्टेशन पर दुनिया का सबसे लंबा स्पेसवॉक पूरा किया।
- शेनझोउ-19 के दल के सदस्य कै जूझे और साँग लिंगडोंग ने स्टेशन के बाहर 9 घंटे तक काम किया, जो 2001 में अमेरिकी अंतरिक्ष यात्री जेम्स वॉस और सुसान हेल्म्स के 8 घंटे 56 मिनट के रिकॉर्ड को तोड़ता है।
- ये दोनों अक्टूबर 2024 में तियांगोंग स्टेशन पहुंचे थे और अप्रैल या मई 2025 में पृथ्वी पर लौटने वाले हैं। इससे पहले, 2024 में ही शेनझोउ-18 के दल ने 8 घंटे 23 मिनट का रिकॉर्ड बनाया था।
- यह उपलब्धि चीन की अंतरिक्ष अन्वेषण क्षमताओं को दिखाती है और लंबे समय तक चलने वाले अंतरिक्ष अभियानों में इसकी नेतृत्व क्षमता को साबित करती है।
- इस रिकॉर्ड के साथ, चीन वैश्विक वैज्ञानिक समुदाय के लिए बहुमूल्य डेटा उपलब्ध करा रहा है और मानव अंतरिक्ष अन्वेषण की सीमाओं को आगे बढ़ा रहा है।



ऊर्जा संरक्षण में उत्कृष्टता के लिए RINL को अवार्ड

- राष्ट्रीय इस्पात निगम लिमिटेड (RINL), जो विशाखापट्टनम स्टील प्लांट संचालित करता है, को आंध्र प्रदेश राज्य ऊर्जा संरक्षण पुरस्कार 2024 में गोल्ड अवार्ड मिला। यह अवार्ड विजयवाड़ा में ऊर्जा संरक्षण सप्ताह के दौरान प्रदान किया गया और इस्पात क्षेत्र में ऊर्जा दक्षता और संरक्षण में RINL के असाधारण प्रयासों को मान्यता दी गई।
- पिछले तीन वर्षों में, RINL ने कई ऊर्जा-बचत उपाय अपनाए हैं, जैसे कि अपशिष्ट ऊर्जा का कुशल उपयोग, जिससे ऊर्जा खपत और पर्यावरणीय प्रभाव को काफी कम किया गया है।
- RINL के प्रयास औद्योगिक क्षेत्रों के लिए टिकाऊ प्रथाओं को अपनाने का एक मजबूत उदाहरण पेश करते हैं। यह अवार्ड न केवल ऊर्जा संरक्षण के प्रति RINL की प्रतिबद्धता को मान्यता देता है, बल्कि भारत के ऊर्जा उपयोग को कम करने और हरित औद्योगिक प्रथाओं को बढ़ावा देने के बड़े लक्ष्य का भी समर्थन करता है।

ऑटोमोबाइल उद्योग के दिग्गज ओसामु सुजुकी का निधन

- सुजुकी मोटर कॉर्पोरेशन के पूर्व अध्यक्ष ओसामु सुजुकी का 25 दिसंबर 2024 को 94 वर्ष की उम्र में मैलिगनेंट लिंफोमा के कारण निधन हो गया।
- उन्होंने 1958 में कंपनी जॉइन की और तेजी से तरक्की करते हुए 1978 में अध्यक्ष और 2000 में चेयरमैन बने।
- उनके नेतृत्व में, सुजुकी ने वैश्विक स्तर पर अपनी पहचान बनाई, खासकर भारत में, जहां मारुति सुजुकी हर घर का नाम बन गया। उनका नेतृत्व नवाचार, किफायती वाहनों और वैश्विक विस्तार पर केंद्रित था, जिसने कंपनी को कॉम्पैक्ट वाहनों के क्षेत्र में अग्रणी बनाया।



Face to Face Centres



30 December 2024

- उनके योगदान के लिए भारत सरकार ने उन्हें 2007 में पद्म भूषण से सम्मानित किया। उनकी विरासत सुजुकी मोटर कॉर्पोरेशन की निरंतर सफलता और ऑटोमोबाइल उद्योग पर उनके वैश्विक प्रभाव में जीवित है।

राजस्थान ने एम-सैंड नीति शुरू की

- राजस्थान सरकार ने 2024 में टिकाऊ निर्माण और बुनियादी ढांचे के विकास को बढ़ावा देने के लिए एम-सैंड नीति लागू की है। एम-सैंड, यानी मैनुफैक्चर्ड सैंड, चट्टानों या पत्थरों को क्रश करके बनाया जाता है और यह प्राकृतिक नदी की रेत का एक विकल्प है।
- एम-सैंड के कई फायदे हैं: यह कंक्रीट की कार्यक्षमता को बढ़ाता है क्योंकि इसमें वे हानिकारक जैविक सामग्री नहीं होती जो सीमेंट की मजबूती और सेटिंग समय को प्रभावित कर सकती हैं। इसके अलावा, यह प्राकृतिक रेत से अधिक मजबूत होता है क्योंकि इसमें मिट्टी और सिल्ट जैसी अशुद्धियां नहीं होतीं।
- यह नीति पर्यावरणीय चिंताओं को भी संबोधित करती है क्योंकि यह नदी की रेत के खनन की आवश्यकता को कम करती है, जो भूजल भंडार को समाप्त कर सकता है और नदी पारिस्थितिकी तंत्र को नुकसान पहुंचा सकता है।
- इस नीति में एम-सैंड को उच्च मानकों पर तैयार करने का प्रावधान है, जिससे यह निर्माण के लिए एक विश्वसनीय और टिकाऊ संसाधन बनता है। यह कदम राजस्थान के बुनियादी ढांचे के विकास और पर्यावरण संरक्षण के बीच संतुलन बनाने के व्यापक प्रयासों का हिस्सा है।

आरबीआई ने पीपीआई के माध्यम से यूपीआई भुगतान की सुविधा दी

- भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) ने घोषणा की है कि प्रीपेड पेमेंट इंस्ट्रुमेंट्स (PPIs), जैसे मोबाइल वॉलेट, डिजिटल वॉलेट और गिफ्ट कार्ड रखने वाले अब यूपीआई के माध्यम से भुगतान कर सकते हैं। पीपीआई ऐसे उपकरण हैं जो लेनदेन के लिए पैसे संग्रहीत करते हैं, जिनमें सामान और सेवाओं की खरीद, भुगतान और प्रेषण शामिल हैं। इन्हें बैंकों और गैर-बैंकिंग संस्थानों दोनों द्वारा जारी किया जा सकता है।
- पीपीआई को दो श्रेणियों में विभाजित किया गया है:
 - » स्मॉल पीपीआई, जिसके लिए न्यूनतम ग्राहक जानकारी की आवश्यकता होती है।
 - » फुल केवाईसी पीपीआई, जो व्यापक लेनदेन की अनुमति देता है।
- पीपीआई को यूपीआई से जोड़ने से उपयोगकर्ताओं के लिए डिजिटल भुगतान करना आसान हो जाएगा और वित्तीय सेवाओं की पहुंच और स्वीकार्यता बढ़ेगी।
- यह कदम भारत के डिजिटल अर्थव्यवस्था और वित्तीय समावेशन के विजन के अनुरूप है, जिससे अधिक से अधिक लोग नकद छोड़कर दैनिक लेनदेन के लिए डिजिटल भुगतान अपनाने के लिए प्रेरित होंगे।

TOP PLAYERS

PPI wallets (in mn)

NON-BANKS

PhonePe	211.82
Mobikwik	141.68
Ola	79.71

BANKS

Paytm*	363.15
Airtel*	37.17
HDFC Bank	33.54

*Payments Bank
Source: RBI



Face to Face Centres

